

शशि थरुर भारत सरकार के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे

यह प्रतिनिधि मण्डल, 22 मई को अमेरिका जायेगा, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 मई। तिरुवन्तपुरम सांसद शशि थरुर द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान तथा बाद में नरेन्द्र मोदी सरकार का बचाव करने पर, जहाँ उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी उनसे अप्रसन्न है, वहीं केन्द्र सरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है, जो अमेरिका को पाकिस्तानी आतंक के विषय में वस्तुस्थिति की जानकारी देगा, भारत सरकार ने पूरी दुनिया को पाक प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी देने की योजना बनाई है।

शशि थरुर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के ऐसे प्रमुख नेताओं के रुपमें 'उपर कर आये हैं, जिन्होंने पहलगाम में हुई हत्याओं के बाद पाकिस्तान पर मोदी सरकार के हमले का जोरदार समर्थन एवं बचाव किया है। थरुर द्वारा किये जा रहे मोदी

- थरुर के अलावा ए.आई.एम.आई.एम. के नेता असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के दूसरे नेता होंगे, जिन्हें प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया जायेगा।
- ओवैसी ने प्र.मंत्री मोदी की सरकार को भारी समर्थन दिया है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार का पाकिस्तान पर जवाबी आक्रमण को।
- हालांकि, शशि थरुर को भारत के प्रतिनिधि मण्डल का अध्यक्ष बनाना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, क्योंकि, थरुर विदेशी मामलात की संसदीय समिति के अध्यक्ष वैसे भी हैं।
- पर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार की कार्यवाही की थरुर द्वारा तारीफ करने को उनका निजी विचार बताकर एक तरह से झिड़की दी थी, इसे देखते हुए शशि थरुर को संसदीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाना साधारण बात नहीं लग रही है।
- ओवैसी के अलावा अमेरिका जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के अन्य सदस्य हैं, शमिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवाड़ी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले व डी. पुरदेश्वरी है।

के समर्थन को कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि कल कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि थरुर अपने

निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो पार्टी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘स्कूल फीस के निर्धारण के लिये अभी तक रिवीज़न कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ?’

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया और सोमवार को अगली सुनवाई तय की

जयपुर, 16 मई (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 19 मई, यानी अगले सोमवार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016 में प्रावधान होने के बावजूद, अभी तक “फीस रिवीज़न कमेटी” का गठन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रमुख शिक्षा सचिव व्यक्तितः या बीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण

- पाठकों को बता दें कि स्कूल फीस की दर तय करने के लिये स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016, के तहत तीन तरह की कमेटियों की अहम भूमिका है। पहली स्कूल फीस कमेटी, जो अध्यापकों और अभिभावकों के प्रतिनिधियों से गठित एक कमेटी होती है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी समझौते से स्कूल फीस की दर तय करती है।
- दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष अगर स्कूल फीस के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह डिवीज़न कमेटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। डिवीज़न कमेटी के फैसले के विरुद्ध आखिरी अपील रिवीज़न कमेटी के समक्ष हो सकती है।

को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। पाठकों को बता दे कि स्कूल

फीस नियंत्रण कानून के अनुसार, हर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में अब जुलाई माह में सुनवाई

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएएस जीएस संघ की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में अब जुलाई माह में सुनवाई करना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह

- पूर्व आईएएस संघू के अधिवक्ता ने बहस पूरी करने के लिये और समय मांगा

आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संघू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, पूर्व आईएएस जीएस संघू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने तीसरे दिन भी बहस जारी रखी। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे बहस के लिए पर्याप्त समय ले चुके हैं और दूसरे वकीलों को भी बहस का मौका दिया जाए। इस पर संघू के अधिवक्ता ने कुछ समय के लिए बहस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अवमानना के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक 20 को अदालत में तलब

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को बीस मई को अदालत में पेश होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स करवाकर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुमन कुमारी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक

- शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को पेश होकर बताना है कि अदालत के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई।

सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में भाग लिया था। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि वह बीएसटीसी न होकर, एनटीटी प्रशिक्षण प्राप्त है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल, 2008 को परिपत्र जारी कर प्रावधान किया कि एनटीटी कोर्स करने वाले छह माह का ब्रिज कोर्स कर बीएसटीसी के समान हो जाएंगे। याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने चिनाब पर बने सलाल व बागलिहार बाँधों से पानी को नियंत्रित किया

पाकिस्तान में हाय-तौबा मची, सिंधु नदी के सिस्टम से ही पाकिस्तान की सिंचाई की 80 प्रतिशत जरूरत पूरी होती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया और संभावित रूप से अस्थिर मोर्चा खुल रहा है जो ज़मीन को लेकर नहीं, बल्कि पानी को लेकर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ने और सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से भारत ने सिंधु नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की सिंचित कृषि भूमि का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है।

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिनाब नदी पर स्थित सलाल और बागलीहार बांधों से जल प्रवाह में बदलाव किया है। इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और इस्लामाबाद ने तुरंत नई दिल्ली को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि पश्चिमी

- भारत के जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है, इंडस वॉटर ट्रिटी के प्रावधानों के तहत भारत को “नॉन कन्ज़म्पटिव” उद्देश्यों के भारत, इंडस वॉटर सिस्टम के पानी का उपयोग कर सकता है, जैसे हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर हाउस चलाना आदि।

- पर, पाकिस्तान के सिंचाई विभाग को कहना है, अगर सिस्टम में पानी छोड़ने की व्यवस्था व टाईम में कुछ भी परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान का सिंचाई का व खेती का “चक्र” (साइकिल) बुरी तरह प्रभावित होगा। और भारी तबाही मच जायेगी।

- पाकिस्तान की यह गुहार भारत के कानों तक पहुँची है। पर, अभी भारत किसी प्रकार “एडजस्टमेंट” करने के मूड में नहीं है, जब तक “आतंकवाद” के निर्यात की पाकिस्तान की नीति नहीं बदलती।

नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब के प्रवाह में किसी भी प्रकार का व्यवधान

संकट से जुड़ रहा है। यह कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त बयान के बाद आया है:

“आतंक और व्यापार, आतंक और बातचीत, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते।”

इस संदेश जिसे कई लोग बड़ा बदलाव मानते हैं, यह दर्शाता है कि अब भारत जल सहयोग को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ रहा है, जो पहले के उस दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है जिसमें सिंधु जल संधि को राजनीतिक तनाव से अलग रखा जाता था।

जम्मू-कश्मीर में स्थित सलाल और बागलीहार बांधों के गेट इन दिनों बंद करने से चिनाब नदी के पाकिस्तान में प्रवाह में बदलाव आया है। साथ ही, भारत ने पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब, पर कई जलाविद्युत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री आवास पर हाईलैवल मीटिंग

नयी दिल्ली, 16 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया।

मोदी की अध्यक्षता में एक घंटे से अधिक समय तक चलायी गई बैठक में शाह के अलावा विदेश मंत्री ड्राँ एस जयशंकर

- मीटिंग में प्र.मंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे।

और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इसके अलावा, आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

+

A black and white photograph showing a group of women in traditional Indian attire (sarees) standing in a line. They are barefoot. To the right, a man in a light-colored uniform stands at attention. The background shows a doorway and some posters on the wall.

- वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करती हैं महिलाएं
- बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदातों को अंजाम देती हैं

मैं सामने आया है कि बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदात को देती हैं। अंजाम और फिर अपने पुरुष सहयोगियों के मार्फत दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर माल को बेच देती हैं। पुलिस पुछताछ में और भी कई वारदातें देखने की आशंका जताई जा रही है।

और वसन को गिरफ्तार किया है। चारों ही महिलाएं एक ही परिवार की हैं और गुजरात हाल खानाबदोश बेनाड रेलवे स्टेशन रहने वाली हैं। पुलिस पूछताछ

C
M
Y
K

को इंटरनैशप कर लेते हैं। इससे गोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कलानिधि भी मेडिकल ऑफिसर और चिकित्सकों को सभी सेवा शर्तें आदिदिगमय पेश करते हैं और दंत चिकित्सक भी अपनी पढ़ाई के बाद एक साल का इंटरनैशप करते हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच परिवर्तनीय काल को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दंत चिकित्सक भी मेडिकल ऑफिसर से समान कार्य कर रहे हैं तो फिर उन्हें भी परिवर्तनीय काल में मेडिकल ऑफिसर के समान भत्ता दिया जाना चाहिए। जिस पर सुनाई करते हुए खंडपन ने संबंधित अधिकारियों से जवाब देकर कहा है।

जयपुरा धाकड़ समाज के युवाओं को संसदित कर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उथ्थान के लिए प्रतियुद्ध श्री धाकड़ महासभा युवा संघ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शुक्रवार को विधितव ऐलान किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधाकण नरेंद्र नारायण निर्देशों पर युवा संघ के राष्ट्रीय अय्धक्ष अर्जुन धाकड़ ने कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। घोषित कार्यकारिणी में विधित पदां कुल 75 से अधिक युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकारिणी में 7 राष्ट्रीय महामंत्री, 8 वरिष्ठ उपाय्धक्ष, 18 राष्ट्रीय उपाय्धक्ष, 12 राष्ट्रीय संसदन महामंत्री,

■ पांच लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से दर्ज की गई थी एफआईआर

मामले में राज्यपाल को स्वयं अपने विवेक से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर पेंसिलान कानूना था। इसलिफ कानूना कायकारता करे खिलाफ मामला में की जाने वाली समस्त कारवायों को रद्द किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपटी ने सर्वोच्च अदिकारिता से जबाब तत्व करते हुए याचिकाकारता के खिलाफ दर्ज एकअदालत में कारवायों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एसबी की टीएम ने राम अवतार गुप्ता को पांच लाख रुपया की रिश्तत के साथ 5 मई, 2022 को पकड़ा था। राम अवतार पर आरोप है कि एक निज को जॉर्जेल में छात्रों की सीटों बढाते की एजम में यह रिश्तत ली थी। एसबी को कुलपति के कमरे से लाखों रुपया की नकदी और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भी बड़ी धरनाशि मिली थी।

+

के मौसम में गड्डों में पानी भरने के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से आमजन को बचाया जा सके। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मोघाणा, एडीशनल एन.पी. एन.एन.एच. जयपुर पुणेन्द्र सिंह, ए.सी.पी. डी.सी.पी. वेस्ट सुन्दर कुमार, ए.सी.पी. कोटावाली उत्तर अनुप सिंह, ए.डी. सी.पी. ईस्ट के.के. अवस्थी, अधीक्षक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग आर.के. सिंह, एस.ई. जे.डी. ए. मोहित चौधरी, एडीशनल डी.सी.पी. साउथ पुनमचन्द विश्नोई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रश्नपत्र। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निधि हस्तान्तरण की नवीन संशोधित प्रणाली को केंद्रों और शीघ्र हस्तान्तरण (एसएफआर) के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शासन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डिजिटल सिचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव ने नवीन प्रणाली में सफलतापूर्वक हस्तान्तरण किए जाने के लिए राजस्थान की प्रेक्षा करते हुए अन्य राज्यों को भी राजस्थान की तर्ज पर उनके प्रदेशों में प्रयोग लाने का सुझाव दिया।

जयपुर। निदेशक अर्जुन संयुक्त शासन समिति बचनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को मंगा छान-छात्रों को तय समयवाधि में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की को की है। इसमें होने वाले विलंब वा समस्या के समाधान के लिए संस्था प्रधान और निदेशक अर्जुन अग्रवाल ने बहसत समय-व्यय के साथ काम कर छात्र-छात्राओं को पहचत पहुँचाए। उन्होंने कहा इसमें कठिनी ती तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

अग्रवाल ने शुक्रवार को सामाजिक कार्य अर्थात् अर्धकारिता विभाग के मुख्यालय अर्धकारि भवन के सभागार

मैं जिले के लगभग 50 सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों और विधायी अधिकारियों के साथ अहम बैचलर कल छात्रवृत्ति प्रक्रिया को आसान बनाने और छात्र-छात्राओं को प्रक्रिया समझाने और उचित परामर्श के निर्देश देने के लिए उन्होंने संस्थान या विद्यार्थी स्तर से समर्थन पर आश्रित विद्याओं को अग्रिम नहीं किए जाने, विद्यार्थियों द्वारा संस्थान में बायोमेट्रिक नहीं किए जाने, विद्यार्थी द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ण नहीं किए जाने संबंधी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के नेहा समस्त संस्था प्रभारी संस्थान तथा राज्य सरकार द्वारा प्रभावित नित्सातरण को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे तथा एक कलैडर तैयार कर छात्रवृत्ति का नित्सातरण को उन्होंने कर काहण विकाषायेण के आवेदनो न लालनमे वाले आक्षेपो के नित्सातरण के संस्थानमे मै एक एसओपी बनाई जाए तथा जिनमे पर्सपेक्टिव जर्ज नही करवाई जा रहै है या बायोमैट्रिक प्रणाली के हार्डसयर, दूरभाष या नोटिफिकेसन्स को कर शीघ्र आक्षेप पूर्ति करवाये

हूए उन्हें भी 50 वर्षों से अधिक समय तक
होगा गया है। पत्रकार जगत सकारात्मक
वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। देश की आजादी के समय
भी पत्रकार जगत ने राष्ट्र में देश भक्ति
की को जगाये रखा। उन्होंने कहा कि
नारद पत्रकारिता के जनक थे। वे संवाद
के संवाहक थे। देवनागी ने कहा कि
आपरेशन सिन्दूर मिशन को पत्रकारों ने
राष्ट्रवाद की भावना के अनुषंग प्रसारित
किया, यह अभिप्रेतनीय है। देवनागी ने
कहा कि आज भारत की विश्व में विशेषता
पत्रकार बनी है। भारत की बढ़ता हुआ
अन्य देश नहीं देख पा रहे हैं। अन्य देशों

की नजरों में भारत के प्रति खूबखटाहट है हमारे देश की ताकत है। नये भारत को श्रेष्ठ बनाने और उसे निरन्तर आगे बढ़ाने में सभी सक्रिय भागीदारों निभाएं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। देवनानी ने कहा कि लोकतन्त्र में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधान सभा में नवीनता लाने के लिए श्रेष्ठ परिवर्तन करने का वे निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। देवनानी ने इसके लिए पत्रकारों से सकारात्मक परामर्श देने के लिए कहा।

परिवादी अभिनव जैन के परिवाद पर अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिये

को मांग जारी रही। उसे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया। वह 19 मार्च 2025 को जब एयरफोर्स स्टेशन बेटे से मिल गया तो पत्नी व ससुर ने उससे पांच करोड़ रूपए व बीएमडब्ल्यू कार की मांग की और उसके बाद ही बेटे से मिलवाने के लिए कहा। परिवार में कहा गया कि उसकी पत्नी व सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया जा सके। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा है।

प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर रोक से खानों में माइनिंग प्लान नहीं स्वीकृत हो सकेंगे

सैकड़ों पुराने खान मालिक ड्रोन सर्वे नहीं कर पा रहे हैं और एसएमई उनका माइनिंग प्लान अनुमोदित नहीं कर रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में अग्रधान खनिज के पट्टाधारियों को 3० जून से पहले अपने क्षेत्र और उसके आसपास का ड्रोन सर्वे कर खान एवं भूविज्ञान विभाग को रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर जिलों सहित पूरे प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा रखा है जिससे सैकड़ों खान मालिकों के माइनिंग प्लान स्वीकृत नहीं हो सकेंगे और खनन रुक जाएगा।

जानकारी के अनुसार सरकार ने 24 अक्टूबर, 24 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध एक अप्रैल, 25 से खान मालिकों के लिए अपने खनन पट्टा क्षेत्र और उसके बाहर 1०० मीटर की परिधि में स्वयं के खर्च पर ड्रोन सर्वे कर वार्षिक रिटर्न के साथ रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान किया है। खान मालिकों को यह रिपोर्ट 30 जून तक पेश करनी होगी तभी अधीक्षण खनि अभियंता उनका माइनिंग प्लान अनुमोदित करेंगे। लेकिन भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव को देखते हुए गुह विभाग के उप शासन सचिव

- बीकानेर में नई खानें शुरू नहीं होने से भी सरकार को डेडरेंट, प्रीमियम राशि, आरएसएमईटी और टीसीएस के दो करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होगा**

- बीकानेर जिले में ही जिप्सम, क्ले, बजरी की ऐसी करीब 75 खानें हैं, इसके अलावा 55 से ज्यादा नए खनन पट्टे दिए जाने हैं जिनकी एलओआई भी जारी कर दी गई, अब खान मालिक ड्रोन सर्वे नहीं कर पाएंगे और माइनिंग प्लान अटक जाएगा**

महेश कुमार शर्मा ने पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य में ड्रोन उड़ाने पर बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर लोगों में लापरवाह बने जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी है।

खानों में काम ठप हो जाएगा। इससे खान मालिक और श्रमिक वर्ग तो संकट में आएगा ही, सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा। बीकानेर में नई खानें शुरू नहीं होने से भी सरकार को डेडरेंट, प्रीमियम राशि, आरएसएमईटी और टीसीएस के दो करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होगा। ऐसे में खनन पट्टाधारक ही नहीं, खान विभाग के अधिकारी भी असमंजस में हैं।

खान विभाग के बीकानेर वृत्त में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते

हैं। इसके अलावा चूरू हनुमानगढ़ जिले भी वृत्त में शामिल हैं। इनमें से केवल बीकानेर जिले में जिप्सम की 36 लीज खाजुवाला, बज्जू के बॉर्डर एरिया में है। 25 लीज तो रेड जोन में ही नहीं, सामान्य दिनों में भी ड्रोन उड़ाना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा बॉर्डर जिलों में सैन्य गतिविधियों का संचालन होता रहता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किमी, एयरस्ट्रिप व आर्मी कैंट एरिया से 3 किमी परिधि, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान से 2 किमी परिधि, आयुध डिपो व बीएसएफ मुख्यालय रेड जोन घोषित हैं। इन इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।

बीकानेर वृत्त के एसएमई एनके बैरवा ने अपने अधीन खनि अभियंताओं से ड्रोन सर्वे पर टिप्पणी मांगी है। एसएमई के अधीन जिलों के अभियंताओं ने भी ड्रोन सर्वे पर रोक के कारण माइनिंग प्लान अनुमोदन के

संबंध में मार्गदर्शन मांगा है।

ड्रोन सर्वे नहीं होने से माइनिंग प्लान अनुमोदित नहीं होने पर खनन मामलों के जानकार देवेन्द्रसिंह धमोरा ने बीकानेर वृत्त के एसएमई एनके बैरवा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन उड़ाने पर रोक कब तक रहेगी, यह निश्चित नहीं है। ऐसे में सरकार को खासकर बॉर्डर जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि माइनिंग प्लान अनुमोदित किए जा सकें।

खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से प्रत्येक पांच साल में खनन पट्टेधारियों से माइनिंग प्लान लिया जाता है जिसमें वे बताते हैं कि किस तरह पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नियमों की पालना करते हुए सुरक्षित तरीके से खनन करेंगे। एमई-एमई और भूवैज्ञानिक माइनिंग प्लान की रिपोर्ट तैयार कर एसएमई को सौंपते हैं। एसएमई माइनिंग प्लान अनुमोदित करता है। इसके अलावा प्रत्येक नए खनन पट्टाधार को माइनिंग प्लान देना होती है। तभी उसे सेंशन मिल पाती है।

ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। झल्लारा थाना पुलिस ने सायबर शौल्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला ने बताया कि आरोपी मुकेश पटेल पिता रामलाल निवासी डगार झल्लारा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुखबि्र से सूचना मिली थी कि डगार तालाब कि पाल के नीचे रोड किनारे झाड़ियों में एक युवक मोबाइल पर एस्कौट सर्विस नाम से लड़कियां उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बबूल की झाड़ियों में एक युवक छिपा हुआ मिला जो पुलिस जाी को देख भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके कब्जे से दो मोबाइल वसिम कार्ड जव्त किए। जांच के दौरान जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें फर्जी लड़की के नाम की इंस्टाग्राम आईडी मिली, जिससे उसके द्वारा कई लोगों से चैटिंग थी। इसी तरह टेलीग्राम एप पर भी 4 अलग-अलग नाम से फर्जी आईडी होना पाया गया, जिसमें लड़की उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से पैसे रेंटने संबंधी मैसेज मिले।

रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई करते हुए खैरथल में तैनात पटवारी अशोक कुमार को एक हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रोगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र मीणा के निर्देशनों में की गई। एसीबी चौकी अलवर को शिकायत मिली थी कि पटवारी अशोक कुमार, परिवारी से उनकी भाभी के बच्चों के नाम पर विरासत का इंतकाल दर्ज कराने के लिए दो हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवारी से पहले पांच सौ रुपये ले लिए थे, जबकि शेष एक हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पटवार भवन पर पटवारी की अनुपस्थिति से आमजन में रोष

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर में आये दिन पटवारियों की मनमानी के चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांगानेरी गेट स्थित पटवार भवन पर लंबे समय तक पटवारी के अनुपस्थित रहने या कार्यालय न पहुंचने की शिकायत को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष फैला है। पटवारी भू-अभिलेखों, जमीन संबंधी दस्तावेजों (जैसे खसरा-खतोनी), और राजस्व विवादों के निपटारे में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी गैर-मौजूदगी में आम नागरिकों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पाती, जिससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जमीन खरीद-विक्री, उत्तराधिकार या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अटकने के कारण लोगों को आर्थिक

- पटवारी की गैर-मौजूदगी में आम नागरिकों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पा रहा है**

नुकसान हुआ है। यही नहीं लोगों का आरोप है कि पटवारी मनमानी शुल्क वसूलते हैं या काम रोककर रिश्वत की मांग करते हैं। कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायतों के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोगों ने पटवारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग या बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाने और अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए की मांग की है।

छात्र लापता, मामला दर्ज

निवाई, (निसं)। पुलिस थाने में शुक्रवार को एक छात्र की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि शिवजीराम शर्मा निवासी जयसिंहपुरा ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका पुत्र निरंजन शर्मा राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में अध्ययनरत है। उसका बुधवार को सीबीएसई बोर्ड

भागवत आज पुष्कर में

अजमेर, (कासं)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार शाम एक विवाह समारोह में शिरकत करने पुष्कर आएंगे। भागवत की पुष्कर यात्रा को लेकर पुलिस द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भागवत शनिवार शाम छह बजे अल्प प्रवास यात्रा के दौरान गनाहेड़ा में स्थित निजी रिजॉर्ट

में आयोजित परिचित के शादी समारोह में शामिल होंगे। भागवत के कार्यक्रम को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह व नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

अजमेर में दो और बांग्लादेशी पकड़े, अब तक 37 डिटेन

अजमेर, (कासं)। जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। एसपी वंदिता राणा के निर्देशों के तहत गंज थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को लगातार सातवीं कार्रवाई करते हुए दो और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है।

- सभी लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी**
- ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है**

गंज थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोंगिया, बाबूगढ़ और आसपास के पहाड़ी इलाकों में दबिश देकर अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को दो और बांग्लादेशी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गंज थाना पुलिस ने अब



गंज थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत दो और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है।

तक इस विशेष अभियान के अंतर्गत 37 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया जा चुका है। बताया गया कि ये सभी लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार इन लोगों से पृष्ठताछ की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें रिमांड होम

के जरिए डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी वंदिता राणा ने जिले के सभी नागरिकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना वैध पहचान दस्तावेजों के संदिग्ध रूप से रह रहा हो, उसकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके तहत खासतौर पर ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

डाटा सेंटर की कम्पनी में निवेश राशि को हड़पने का आरोपी गिरफ्तार

निवाई/टोंक, (निसं)। निवाई थाना पुलिस ने डाटा सेंटर की कम्पनी में निवेश करने का प्रलोभन देकर निवेश राशि को हड़पने के दो साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि 7 सितम्बर 2023 को परिव्रादी नेहनुलाल गुर्जर निवासी दीनदयाल कॉलोनी ने डाटा स्पेश खरीदे एवं बदले में 12 साल तक 29 हजार 1०0 रूपए देने का प्रलोभन देकर परिव्रादी के साथ धोखाधड़ी करने वाली सीनाव क्लाउड टेक्नोलोजी प्रा. लि. के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया था। जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी के निर्देशन एवं डीवाईएसपी मृत्युन्जय मिश्रा के सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने दिल्ली, आगरा, फरीदाबाद व गाजियाबाद सहित कई शहरों में आरोपियों की तलाश की। आरोपी की तलाश के लिए मुखबिरी की सूचना को तत्कनीक संसाधनों एवं फिल्ड आसूचना के आधार पर आरोपी अनुज कुमार त्यागी पुत्र कांति प्रसाद त्यागी निवासी बैंक कॉलोनी गोविन्दपुरम



पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

गाजियाबाद थाना मधुवन बापूधाम जिला गाजियाबाद उत्तरप्रदेश हाल निवासी रॉयल गार्डन थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उत्तरप्रदेश को धोखाधड़ीपूर्वक हड़पता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरूद्ध कवि नगर जिला गाजियाबाद में दो मामले दर्ज हैं।

थार गाड़ी की चपेट में आने से दो की मौत, एक घायल



जालोर शहर के निकट बिशनगढ रोड पर थार की टक्कर से दो जनों की मौत हो गई।

जालोर, (कासं)। जालोर शहर के बिशनगढ रोड पर शुक्रवार को एक थार गाड़ी (जीप) की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा थार जीप चालक घायल हो गया, जहां उन्हें जालोर के राजकिय चिकित्सालय में लाया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया।

जालोर शहर के निकट बिशनगढ़ रोड चुंगी नाका के पास बिशनगढ़ से जालोर की तरफ आ रही था। जीप के चालक ने वाहन को तेजगति से चलाते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे आगे चल रही मोटरसाइकिल पर सवार पहाड़पुरा

- सीट बेल्ट लगे होने के कारण दोनों एयरबैग खुल गए, जिस कारण गाड़ी में सवार दोनों युवकों की जान बच गई**

निवासी भरत चौधरी पुत्र मीठालाल व मनोहर चौधरी पुत्र रावताराम की मौके पर मौत हो गई जबकि थार जीप चालक गोपाल देवासी निवासी एलाना घायल हो गए। गाड़ी इतनी तेज गति थी कि चालक गोपाल देवासी एलाना उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराते हुए हाइवे पर

लगे संकेतक बोर्ड के पिलर से टकरा गई। सीट बेल्ट लगे होने के कारण दोनों एयरबैग खुल गए, जिस कारण गाड़ी में सवार दोनों युवकों की जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस थानाधिकारी अरविंद पुरोहित, एएसआई रामूराम जाणी समेत पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। परिजनों को सूचित किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर एम्बुलेंस 1०8 की सहायता से जालोर के राजकिय चिकित्सालय में लाया गया। कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरु की।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने के आदेश

- वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान विषय की विचारित सूचियों में सफल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे**

माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्कूटनी-अप्नाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भंरो। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑफ़न पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) माय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होंवें। इस हेतु

संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संचालित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अभिस्तानित किये जायेंगे।

दूरसंचार विभाग को जमा सिक्योरिटी राशि देने सहित दस हजार का जुर्माना लगाया

- राशि नहीं लौटाने पर परिव्रादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग में परिवाद पेश किया**

में परिवाद पेश कर बताया कि सन् 2०01 में अपने घर पर दूरसंचार विभाग से लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्शन ले रखा था। लैण्डलाइन की आवश्यकता नहीं होने पर परिव्रादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिसम्बर 2०14 में उक्त लैण्डलाइन कनेक्शन विच्छेद कर दिया। उस समय दूरसंचार विभाग जालोर के अधिकारियों

ने अवगत करवाया कि उक्त कनेक्शन को लेकर सिक्योरिटी राशि 2865 रुपये सिरोही कार्यालय से आपके खाते में जमा हो जायेंगे लेकिन परिव्रादी द्वारा बार-बार दूरसंचार विभाग जालोर व सिरोही को सिक्योरिटी पेटे जमा डिपोजिट राशि लौटाने का आग्रह किया, लेकिन डिपोजिट राशि नहीं लौटाने पर परिव्रादी ने जिला

उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग में परिवाद पेश किया। आयोग के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को आदेश दिया कि दूरसंचार विभाग परिव्रादी कांतिलाल भण्डारी को जमा सिक्योरिटी पेट राशि 2865 रुपये परिवाद पेश करने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज के अदा करने के साथ दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

पुजारी की हत्या करने का आरोपी रिमांड पर

रायपुर पुलिस के अनुसार, रायपुर कस्बे में चामुंडा माता मंदिर के पुजारी सुखानाथ (62) पुत्र राजपुर निवासी पिंदू पुत्र नगजीराम सैन ने हनुमानजी की गदा से ताबड़तोड़ हमला किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। मु्तक के भतीजे केमूनिथा निवासी लक्ष्मण पुत्र बैरूनाथ योगी ने पिंदू सैन के खिलाफ जानलेवा हमला कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को ही आरोपित पिंदू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को शुक्रवार को रायपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन रिमांड पर भेज दिया गया।

पुजारी की हत्या करने का आरोपी रिमांड पर

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर में वे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे व करणी माता की पूजा-अर्चना करेंगे

बीकानेर/जयपुर, 16 मई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे और जिले के देशनोक में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर जवानों के साहस और पराक्रम को नमन करेंगे।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर दोपहर 1:10 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 1.15 बजे प्रस्थान कर, वे दोपहर 1:35 बजे रिड्ढि सिड्ढि भवन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:35 बजे यहां से प्रस्थान कर सायं 4 बजे वे पलाना गांव में एक

■ **मुख्यमंत्री जयपुर से बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर दोपहर 1:10 बजे पहुंचेंगे तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सायं 7:20 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिये प्रस्थान करेंगे।**

स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद सायं 5:10 बजे देशनोक के करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद, देशनोक में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यहां से सायं

6:30 बजे प्रस्थान कर सायं 7:15 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा सायं 7:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले की जवाबी कार्रवाई “आपरेशन सिंदूर” में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था। इस ऑपरेशन की गौरवमयी सफलता पर देशभर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बीकानेर के देशनोक में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान, मुख्यमंत्री देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे।

जगदुरू रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ सम्मान

नयी दिल्ली, 16 मई । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां एक समारोह में संस्कृत के विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने इस अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार को भी बधाई दी जो अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने गुलजार जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

मुर्मु ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है।

गुजरात समाचार, मालिक, बाहुबलि शाह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने भारी ‘‘साज़िश’’ बताया

■ **पत्रकारिता से जुड़े लगभग सभी संगठन व संस्थाओं, जैसे प्रेंस क्लब ऑफ इण्डिया, वुमन्स प्रेंस कॉर्प्स प्रेंस एसोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड, ईवेली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरला यूनियन ऑफ वॉर्किंग जर्नलिस्ट्स आदि ने गुजरात के सबसे बड़े व प्रमुख अखबार के मालिक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को ‘‘जनता की आवाज़’’ दबाने की साज़िश बताया।**

अखबार गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया है, जो बेहद शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। यह गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है, क्योंकि इस अखबार ने पिछले 25 वर्षों से मोदी-शाह की नीतियों की आलोचना कर दिखाई है।

शाह बंधुओं के घर और दफ्तरों पर ईडी और इनकम टैक्स छापों के बाद गिरफ्तारी हुई है।

प्रख्यता गुजराती पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्य शीला भट्ट ने एक्स पर लिखा, ‘‘सरकार द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर कदम है। गिरफ्तारी के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली शाह को जांच के लिए सरकारी वी.एस. अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, और फिर उन्हें ज़ायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, श्रेयांश शाह ज़ायडस अस्पताल में बाहुबली शाह की देखभाल कर रहे हैं। श्रेयांश शाह ने मीडिया को बताया कि वे ‘‘लड़ाई जारी रखेंगे।’’ दोनों भाईयों के पास अखबार के अलावा अन्य व्यवसाय भी हैं। श्रेयांश शाह को गुजरात की राजनीति का सबसे तेज दिमाग माना जाता है।’’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आधिकारिक विचार नहीं हैं।

थरूर को प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाये जाने की केन्द्र सरकार की पेशकश को नुकसान रहित सामान्य प्रक्रिया माना जा रहा है, क्योंकि वे विदेशी मामलों से सम्बंधित संसद की स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, भले ही कांग्रेस के कुछ ग्रुप इसे, इस पूरे घटनाक्रम में एक राजनैतिक संदेश के रूप में देख रहे हों। थरूर के लिये राहत की बात यह है कि स्वयं कांग्रेस ने भी इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है, जो यूरोप के विभिन्न देशों सहित, अन्य कई देशों में जायेगा तथा वहाँ पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने आज इस बात की पुष्टि कर दी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू ने इस सम्बंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे से बात की थी तथा ‘‘कांग्रेस निश्चित रूप से

इस (प्रतिनिधिमंडल) का हिस्सा रहेगी।’’ थरूर ने स्वयं भी इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाया है। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सरकार से कह दिया था कि वह इस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी से बात करे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिन्दूर और उसके बाद की स्थिति पर उनके विचार उनके ‘‘निजी विचार’’ थे।

कई प्रतिनिधिमंडल, जिनमें से प्रत्येक में 5-6 सांसद होंगे, विभिन्न देशों में जाकर पाक-समर्थित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। आशा की जा रही है कि ये प्रतिनिधिमंडल 22 मई को भारत से रवाना होंगे तथा जून के प्रथम सप्ताह में वापस आ जायेंगे। इनमें शामिल सम्भावित सांसद हैं- समिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, समित्त पात्रा, सुप्रिया सुले तथा डी. पुरन्देश्वरी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और सुनने का निवेदन किया। इस दौरान, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले को सुनवाई जुलाई माह में रखी है। गौरतलब है कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। जमीन तय सीमा से अधिक होने के कारण जेडीए ने साल 2005 में प्रकरण राज्य सरकार को भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने पट्टा देने से इनकार कर दिया। वहीं, साल 2009 में आवेदन होने पर जेडीए ने मामले को पुनः राज्य

सरकार के समक्ष भेजा। राज्य सरकार ने साल 2011 में पट्टा जारी कर दिया, जिसे साल 2013 में निरस्त कर दिया गया। वहीं, रामशरण सिंह ने साल 2014 में एसीबी में शिकायत दी थी।

मामले में हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई रद्द करते हुए, तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के इन आदेशों को रद्द कर पुनः छह माह में सुनवाई पूरी करने को कहा था।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पुणे गए, वहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी. सतीश से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी माता स्नेहप्रभा वेलंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका हाल ही में निधन हो गया था।

अवमानना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 जनवरी, 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह प्रदेश या अन्य राज्य से याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स कराए और पद खाली होने पर उसे नियुक्ति दे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को न तो ब्रिज कोर्स कराया और न ही उसे नियुक्ति दी। ऐसे में दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों को दंडित कर अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है।

तीन माह में न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाए

- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को दिए निर्देश में भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम बनाने की हिदायत दी।**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट्स व राज्य सरकारें इन नियमों में अपनी जरूरत के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।**

नयी दिल्ली, 16 मई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवा को देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे न्यायालय प्रबंधकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के.एस.के. की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के.एस.के. की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के.एस.के. की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

बलूच नेताओं ने हिन्दुस्तान में ‘‘गवरमेंट इन ...

■ **रज्जाक बलूच के अनुसार, बलूचिस्तान की क्वेटा में कैन्ट्रूमेंट के अलावा पाकिस्तानी सेना की कोई चहल कदमी नहीं है, बलूचिस्तान में, और धीरे-धीरे बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम ज़मीन पर काफी फैल गया है तथा स्वतंत्रता संग्राम को सफलता शीघ्र ही जरूर मिलेगी।**

आज़ादी का यह आंदोलन सफल होगा और पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया जाएगा। बलूच नेता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए एक संगठित निर्वासित सरकार के गठन की योजना बना रहे हैं। रज़्जाक बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान भू-राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी स्वतंत्रता पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता ला सकती है।

महरंग बलूच और अन्य कई नेता बलूचिस्तान में ज़मीन पर काम कर रहे

ज्ञातव्य है कि इस महीने ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के मामलों में आरोप लगाने के पैटर्न पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति अभय ओका ने 2,000 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, हमने की कई शिकायतें देखी हैं। इसमें एक पैटर्न है, केवल आरोप लगाना, किसी ठोस संदर्भ के बिना।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के प्रमुख अखबार गुजरात समाचार पर रेड और कंपनी के निदेशक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी, लोगों की आवाज़ छीनने की कोशिश है। क्या भाजपा सरकार चाहती है कि कोई विपक्ष न हो, कोई मीडिया न हो और जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई न हो? उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है और जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता।

गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रेंस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेन प्रेंस कॉर्प्स, प्रेंस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरल यूनियन ऑफ वॉर्किंग जर्नलिस्ट्स,

वॉर्किंग न्यूज़ कैमरा पर्सन एसोसिएशन ने कहा कि यह कार्रवाई भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक गंभीर हमला है।

प्रेंस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया कि गुजरात समाचार, जो स्वतंत्र पत्रकारिता की लंबी विरासत रखने वाला एक सम्मानित प्रकाशन है, गुजरात और उसके बाहर के लोगों की एक सशक्त आवाज़ रहा है। बयान में कहा गया, ‘‘एक बार फिर, ईडी की गिरफ्तारी मीडिया हाउसों को दबाने और असहमति की आवाज़ों को खामोश करने के लिए राज्य तंत्र के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है।’’

बयान में यह भी कहा गया कि ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा बार-बार मीडिया की निशाना बनाना संविधान में निहित लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के कमजोर करता है और संजानों में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाता है।

गौतम लाहिड़ी ने आरोपों के बारे में पूरी पारदर्शिता की मांग करते हुए, अधिकारियों से प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के शासन के पालन की अपील की।

बयान में कहा गया कि लोकतंत्र में सत्ता की जवाबदेही तय करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया को कुचलना तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना बंद होना चाहिए। अंत में, बयान में सरकार से प्रेंस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और बाहुबली शाह को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जब तक कि पारदर्शी तरीके से कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश न किया जाए।

सेना के रक्षा बजट में 5 0 हजार करोड़ रु. की वृद्धि

इसके बाद कुल रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगा

■ **समझा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार यह कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।**

नई दिल्ली, 16 मई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रक्षा बजट को 5 0 हजार करोड़ रुपये का बूस्ट देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप, भारत के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह वृद्धि संभवतः अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, यह वृद्धि कुल रक्षा आवंटन को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1

में 9.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बढ़े हुए बजट का उपयोग संभवतः अनुसंधान और विकास, तथा हथियार, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मानी जाएगी।

डिफेंस सेक्टर पर 2014 से ही नरेन्द्र मोदी सरकार का फोकस रहा है। भाजपा सरकार के पहले बजट 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। वर्तमान आवंटन सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और कुल बजट का 13 प्रतिशत है।

भारत की रक्षा तैयारी और (संभावित) बजट आवंटन में वृद्धि, पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हुई है। यह विशेष रूप से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर एतैयबा के आतंकी शिबिरों को निशाना बनाया गया था

राजनीतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विलय की वार्ता गोपनीय रूप से चल रही है। नतीजे अनिश्चित है। जहाँ राजनैतिक जरूरत दोनों गुटों को पास ला रही है, वहीं अहं का टकराव व कई ऐसी शिकायतें हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ है और ये बड़ी बाधा पैदा कर रही हैं।अभी महाराष्ट्र का राजनैतिक परिदृश्य बेहद नाजुक है। देखना यह है कि क्या पुराने घावों और वैचारिक मतभेदों पर व्यवसायिक हितों और पारिवारिक रिश्तों को तबज्जो मिलेगी।

छावनी से बाहर नहीं निकल सकती। बलूच नेताओं का कहना है कि उनका प्रबंध अपनी मातृभूमि पर अधिकार संचार करने का है। रज़्जाक बलूच और अन्य बलूच नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूच युवाओं का नरसंहार कर रही है। उन्होंने बताया कि बलूच नेता अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी एक सशक्त अभियान चला रहे हैं। बलूच नेता यह भी कह रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब के पंजाबी लोगों का बलूचों या अरब देशों से कोई डीएनए या सांस्कृतिक संबंध नहीं है। पंजाबी और मिडिल ईस्ट लोगों में कोई कनेक्शन नहीं है। उनको विश्वास है कि वे अपने आत्म-निर्णय के अधिकार को अवश्य हासिल करेंगे। उनका यह भी कहना है कि सिंध, पख्तुनिस्तान और बलूचिस्तान को आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता की अनुमति दी जानी चाहिए।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेंस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आइ. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पालपाया हाऊस, छत्रपति शाहीबाग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्या, बीकानरा। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, अजमेर कार्यालय: आरुह मैन रोड आराध, जयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-241046, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रतु भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी/163, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चुरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908